

प्रपक,

आर०डी०फर्लीवाल,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा० उत्तरांचल उच्च न्यायालय,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग : 2

देहरादून : दिनांक : 27 नवम्बर, 2006

विषय: सिविल जज(जू०डि०), रामनगर, जिला नैनीताल में आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण के पुनरीक्षित आगमन के विरुद्ध विलीय वर्ष 2006-07 में धनराशि को स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1693/यू०एच०सी०/एडमिन०/निर्माण/2005, दिनांक 30.6.06 एवं पत्र संख्या 2198/यू०एच०सी०/एडमिन०/निर्माण/2006, दिनांक 24.8.06 के सम्बन्ध में शासनार्देश संख्या 71-सो/न्याय विभाग/2002, दिनांक 4.7.2002 के अनुक्रम में शासनार्देश संख्या 25-सो(1)/XXXVI(1)/2006-71-सो/02, दिनांक 4.9.2006 को निरस्त करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है सिविल जज(जू०डि०), रामनगर, जिला नैनीताल में आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु पूर्व अनुमोदित लागत रुपये 92,54,000/- के सापेक्ष पुनरीक्षित रुपये 1,10,00,000/- (रुपये एक करोड़, दस लाख मात्र) की लागत पर प्रशासकीय एवं विलीय अनुमोदन प्रदान करते हुए पुनरीक्षित लागत के विरुद्ध अवशेष अतिरिक्त धनराशि रु 17,46,000/- (रुपये सत्रह लाख छियालीस हजार मात्र) की धनराशि को व्यय करने जाने की महामहिम राज्यपाल निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) आगमन में उल्लिखित दरों का निरन्तर विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को, जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव में ली गई हो, की स्वीकृति निम्नानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा ।
- (2) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगमन/धार्मिक गठित कर निम्नानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय ।
- (3) कार्य को स्वीकृत लागत में ही पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा की स्थिति में लागत के पुनरीक्षण के लिए शासन द्वारा कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी ।
- (4) एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगमन गठित कर निम्नानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त कार्य टेकअप किया जाय ।
- (5) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित किया जाय ।
- (6) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य कर ली जाय । निरीक्षण के पश्चात् आवश्यकतानुसार निर्देश तथा निरीक्षण टिप्पणों के अनुरूप कार्य किया जाय ।
- (7) आगमन में धनराशि जिन मदों हेतु स्वीकृत की गई है, उसी मद में व्यय की जाय । एक मद की राशि दूसरी मद में किसी भी दशा में व्यय न की जाय ।

- (8) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा लिया जाय तथा उपयुक्त पाया जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय ।
- (9) जी०पी०डब्ल्यू फार्म 9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पन्नित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगपन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जाएगा ।
- (10) कार्य से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर पर्यज कलस, निष्पन्नता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेश एवं तद्विषयक अन्य आदेशों का अनुपालन किया जाय । कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेंसी/अधिरासी अभियन्ता पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे ।
- (11) निर्माण कार्य कराते समय अथवा आगपन गठित करते समय मुख्य सचिव, उत्तरांचल के शासनादेश संख्या 2047/XVI/219(2006), 30.5.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।
- (12) स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31.3.2007 तक पूर्ण उपयोग कर स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जाय ।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यव वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आव-व्यय के अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "4059-लोकनिर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य भवन-051-निर्माण-00-आयोजनागत-03-न्यायिक कार्य हेतु भवनों का निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जाएगा ।

3- यह आदेश वित्त अनुभाग-5 के अग्रामकीय संख्या-697/XXVII(5)/2006, दिनांक 21.11.06 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(आर०डी०पालीवाल)
सचिव ।

संख्या-58-दो(1)/XXXVI(1)/2006-71-दो/02 तदुद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), ओवरगैर बिल्डिंग, उत्तरांचल, गाजरा, देहरादून ।
2. मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून ।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल ।
4. मुख्य अभियन्ता, स्तर-1, लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल, देहरादून ।
5. अधिरासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रामनगर, नैनीताल ।
6. नियोजन विभाग/वित्त अनुभाग-5, उत्तरांचल शासन ।
7. एन०आई०सी०/सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/गार्ड फाईल ।

आज्ञा में,

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव ।